



2026:AHC-LKO:40565

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 4030 वर्ष 2026

कौशल

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राजेश कुमार शर्मा, दीपाली प्रजापति, प्रभु

शरण, रजत कुमार शर्मा

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2026, धारा 109, 115(2) भा०न्या०सं, पुलिस स्टेशन औरस, जिला उन्नाव में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह मात्र एक दुर्घटना का मामला है, लेकिन प्रथम सूचना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रिपोर्ट बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने घायल व्यक्ति का गला जान से मारने की नीयत से दबाया था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक निवेदन किया कि चिकित्सा-कानूनी आख्या में ऐसी कोई चोट नहीं पाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि चोट मामूली प्रकृति की है, फिर भी जांच अधिकारी द्वारा आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। अंत में उन्होंने निवेदन किया कि निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है और आवेदक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, 09.03.2026 से जेल में है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध करते हैं, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं करते कि चोटें मामूली प्रकृति की हैं।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट, घायल व्यक्ति के बयान, चिकित्सा-कानूनी आख्या और अन्य संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करने से यह स्पष्ट है कि घायल व्यक्ति के शरीर पर मामूली चोटें आई हैं। ऐसी स्थिति में, न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।

7. आवेदक कौशल को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2026 में 20,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, अधीनस्थ न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही कर सकती है।
- (v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भा०ना०सु०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 209 भा०न्या०सं० के तहत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।
- (vi) आवेदक (क) मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (ख) आरोप तय करने; और (ग) धारा 351 भा०ना०सु०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि अधीनस्थ न्यायालय की राय में आवेदक की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय जमानत रद्द करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

जून 9, 2026

वीकेएस

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।